

**न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या - 03**

**बीकानेर**

**सरकार**

**बनाम**

**रजनीश पाठक**

**एफआईआर संख्या - 0168/2020 पीएस महिला, बीकानेर**

**आपत्ति प्रार्थना पत्र - परिवादिया के निजी अधिवक्ता के द्वारा न्यायहिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने हेतु**

महोदिया,

अप्रार्थी रजनीश पाठक द्वारा निम्नलिखित पेश है :

1. आज अप्रार्थी रजनीश पाठक की दिनांक पेशी है।
2. यह की यह मुकदमा सरकार बनाम रजनीश पाठक है जिसमे सरकार की तरफ से APO साहब व अप्रार्थी अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता चन्द्रशेखर हर्ष जी उपस्थित है।
3. यह की महिला थाना द्वारा यह मुकदमा परिवादिया शिवांगी पाठक के परिवाद पर दिनांक 05/12/2020 को दर्ज कर दिनांक को आरोप पत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया था।
4. जिस दिन से आरोप पत्र दिनांक को पेश हुआ है परिवादिया शिवांगी पाठक स्वयं आज दिन तक न्यायलय में उपस्थित नहीं हुई है तथा परिवादिया शिवांगी पाठक के निजी अधिवक्ता द्वारा न्यायहिक प्रक्रिया चलाई जा रही है।
5. दिनांक को परिवादिया शिवांगी पाठक के निजी अधिवक्ता द्वारा सीआरपीसी 190 की धारा के तहत आवेदन पेश हुआ है जबकि उपरोक्त आवेदन पर न तो शिवांगी पाठक के हस्ताक्षर हैं और न ही इस अदालत से व्यक्तिगत वकील नियुक्त करने के लिए पूर्व अनुमति का अनुरोध किया गया है तथा अनुमति के बिना ही परिवादिया शिवांगी पाठक के निजी अधिवक्ता द्वारा न्यायहिक प्रक्रिया चलाई जा रही है।
6. यह की सीआरपीसी की धारा 225 के मुताबिक "विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना — सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा"।

परिवादिया शिवांगी पाठक के निजी अधिवक्ता द्वारा विचारण में संचालन कर धारा 225 सीआरपीसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

7. परिवादिया के अधिवक्ता जो की बीकानेर न्यायालय के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित अधिवक्ता है और पूर्ण तरीके से कानून के जानकार है, उनके द्वारा बिना न्यायालय के अनुमति से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दे कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा हैं।

8. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील नंबर 1727 / 2019 "रेखा मुरारका बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अन्य" के आदेश दिनांक 20/11/2019 के मद संख्या 9 के अनुसार:-

“225. In every trial before a Court of Session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor, 301(1) .....

(2) If in any such case any private person instructs a pleader to prosecute any person in any Court, the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the directions of the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor, and may, with the permission of the Court, submit written arguments after the evidence is closed in the case. “

8. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, भोपाल सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2001 CriLJ 912 2001 (1), WLN 166) में, राज्य के मामलों में सरकारी वकील, निजी वकील और शिकायतकर्ता की भूमिका को स्पष्ट कर दिया गया, आदेश दिनांक 02/08/2000 के मद संख्या 8 के अनुसार:-

“ 8. Thus, in all prosecutions, the State is the prosecutor and a proceeding is always treated as proceeding between the State and he accused. The anxiety of the State is to secure peace and security and has a right to prosecute. The complainant has no independent right to have guilty person punished. It is felt necessary in the larger public interest to save the people from prosecution by a private party.

.....

.....

also harassment during the trial. Complainant has also been given limited right to speak during trial by way of submitting written arguments under Section 301(2) and assist the public prosecutor through private counsel with permission of the Court if the facts so permit under Section 302 CrPC.”

अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से निवेदन है की परिवादिया शिवांगी पाठक के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोका जाये व न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने हेतु उचित आदेश दिया जाये।

दिनांक :

अप्रार्थी

रजनीश पाठक

S/o श्री राधेश्याम पाठक

निवासी - लक्ष्मी नगर दिल्ली